



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2009/श्रावण 20, 1931

No. 265]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2009/SRAVANA 20, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना (निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2009

**विषय :** जापान तथा थाईलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनॉल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

फा. सं.14/27/2009-डीजीएडी.—यतः हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (जिन्हें एतदपश्चात आवेदक कहा जाएगा) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा जाएगा) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम 1995 (जिन्हें एतदपश्चात नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने थाईलैण्ड तथा जापान (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनॉल (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के कथित पाटन का आरोप लगाया है तथा संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जांच शुरु करने का अनुरोध किया है । मै. एस.आई. ग्रुप इंडिया लि. द्वारा इस अनुरोध का समर्थन किया गया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपस्थित हैं और एतद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं ।

### **विचाराधीन उत्पाद**

3. जांच हेतु विचाराधीन उत्पाद फेनॉल है, जिसे कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। इस उत्पाद का विपणन दो ग्रेडों में किया जाता है - रवेदार तथा नमीयुक्त। दोनों ग्रेडों में फेनॉल के बहाव संबंधी विशेषताओं के आधार पर भेद किया जाता है। फेनॉल का उपयोग फेनॉल फॉर्मेलिहाइड रेजिन्स, लैमिनेट्स, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिस फेनॉल - ए एल्किल फेनॉल भेषजों, डिन्फेनिल ऑक्साइड इत्यादि के विनिर्माण में किया जाता है।

4. फेनॉल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि अध्याय 27 के तहत भी आयातों की सूचना प्राप्त हुई है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 तथा 2707.60 के तहत भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तथापि, ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं तथा किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

### **घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति**

5. याचिका मै. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. द्वारा दायर की गई है तथा इसे मै. एस आई ग्रुप इंडिया लि. द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। देश में संबद्ध वस्तुओं के केवल दो ज्ञात उत्पादक हैं। आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारतीय उत्पादन में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. का हिस्सा अप्रैल, 08-सितंबर, 08 के दौरान 58% तथा अक्टूबर, 08-मार्च, 09 के दौरान 55% तथा समर्थनकर्ता के साथ भारतीय उत्पादन का हिस्सा 100% बनता है। अतः आवेदक वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ "घरेलू उद्योग" होगा।

6. उपर्युक्त की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक नियम 2 के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन उपर्युक्त नियमों के नियम 5 के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

### **शामिल देश**

7. वर्तमान जांच में शामिल देश थाइलैण्ड एवं जापान है।

### **समान वस्तु**

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित फेनॉल तथा संबद्ध देशों से निर्यातित फेनॉल में कोई विशेष अंतर नहीं है। वास्तविक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में दोनों उत्पाद तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और दोनों की विशेषताएं काफी समान हैं। आगे यह दावा किया गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा दोनों उत्पादों का अदल-बदल कर इस्तेमाल किया गया है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, पाटनरोधी नियमों के अर्थों के भीतर आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान घरेलू वस्तु" माना जा रहा है।

**सामान्य मूल्य**

9. थाईलैंड तथा जापान में घरेलू बिक्री के संबंध में आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में आवेदक ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्टया विचार किया है जो थाईलैंड के संबंध में दावा की गई उच्च ब्याज लागत में समायोजन के अध्यक्षीन है तथा जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा इसी पर विचार किया गया है।

**निर्यात कीमत**

10. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसूचना सेवा (आईबीआईएस), मुंबई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का दावा किया गया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्ययों तथा अंतर्देशीय भाड़े तथा समुचित सीमा तक इन्हें घटकाकर निकाली गई राशि, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः अपनाया जाता है, इत्यादि के आधार पर कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं हेतु आवेदक द्वारा दावा की गई निर्यात कीमतों के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

**पाटन मार्जिन**

11. संबद्ध देशों के संबंध में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि थाईलैंड तथा जापान में इस प्रकार आई संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

**क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

12. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक से क्षति नहीं हुई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

- i. संबद्ध वस्तुओं का आयात प्रमुखतः जापान, थाईलैंड तथा ऐसे देशों से किया जा रहा है जिनमें शुल्क पहले से लागू है। अन्य देशों से आयात मामूली है।
- ii. पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में मांग में कुछ कमी आई है परंतु यह वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 की तुलना में काफी अधिक है। यद्यपि मांग में कमी हुई तथापि, संबद्ध आयातों के समग्र अर्थों में तथा मांग एवं उत्पादन के संबंध में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

- iii. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं आया है अतः उससे क्षति होने की संभावना नहीं है ।
- iv. ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधकारी उपाय मौजूद नहीं है, जिसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो ।
- v. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अतः यह क्षति का कारक नहीं है ।
- vi. आवेदक के पास संबद्ध उत्पाद हेतु विशेष निर्यात कार्यकलाप का विवरण मौजूद नहीं है । अतः आवेदक के निर्यात निष्पादन से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।
- vii. आवेदक की उत्पादकता में केवल पाटन के कारण गिरावट आई है ।

13. आवेदक ने निवेदन किया है कि एक बार यह विदित होने के पश्चात कि पाटित आयातों के कारण एक प्रतिकूल मात्रा एवं कीमत प्रभाव पड़ रहा है तथा पाटित आयातों के प्रभाव मौजूद हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्षति, पाटित आयातों के कारण नहीं हो रही है, एकमात्र आधार अनारोपण विश्लेषण है अर्थात् यह कि क्षति अन्य कारकों की वजह से हुई है । चूंकि अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों की वजह से क्षति का होना प्रमाणित नहीं होता है, अतः एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों सहित अनेक स्रोतों से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है । यद्यपि उपर्युक्त मानदंडों से यह निर्धारित होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं हुई है । तथापि, आवेदक ने यह निवेदन किया है कि निम्नलिखित मानदंडों से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है ।

- (क) संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।
- (ख) पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट आई थी ।
- (ग) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई थी ।
- (घ) घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट के कारण लाभ में गिरावट आई तथा इसके परिणामस्वरूप नकद प्रवाह तथा घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय में भी गिरावट प्रदर्शित हुई ।

14. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है ।

### पाटनरोधी जांच की शुरुआत

15. उपर्युक्त पैराग्राफों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव की जांच करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं ।

### जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2008 से 30 जून, 2009 (9 महीने) तक की है । तथापि क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा जांच की अवधि शामिल होगी ।

### सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश के निर्यातकों, उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी),**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग,**  
**भारत सरकार**  
**कमरा सं. 240, उद्योग भवन,**  
**नई दिल्ली- 110107**

18. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जो पाटन, क्षति तथा कारणात्मकता से संबंधित जांच से संगत सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकती है ।

2921 GI/09-2

### समय सीमा

19. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना प्राधिकारी को लिखित में इस प्रकार भेजा जाए ताकि वह उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। तथापि, जिन निर्यातकों एवं आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

### सूचना प्रस्तुत करना

20. नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की राय में सूचना को सारांश में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो इसके कारण दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई हितबद्ध पार्टी अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2009

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from Japan & Thailand.**

F.No.14/27/2009-DGAD.—Whereas Hindustan Organic Chemicals Ltd. (herein after referred to as applicant) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (herein after referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules), alleging dumping of Phenol, (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from Thailand and Japan, (herein after referred to as "subject countries") and requested for initiation of Anti Dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods. The request is supported by M/S S I Group-India Ltd.

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject Countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

### **Product Under Consideration**

3. The product under consideration for the investigation is Phenol, also known as Carbolic Acid. The product is marketed in two grades Crystalline and Hydrated. The two grades are differentiated on the basis of flow characteristics of Phenol. Phenol is used in the manufacture of Phenol formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A alkyl Phenols Pharmaceuticals, Dephenyl Oxide etc.

4. Phenol is a basic organic chemical, normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. However, imports are reported under Chapter 27 also. The product is classifiable under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.60. The Customs classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

### **Domestic Industry and Standing**

5. The application has been filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited and supported by M/S S I Group-India Ltd. There are only two known producers of the subject goods in the Country. According to the information provided in the application, the production of Hindustan Organic Chemicals Limited constitute 58% of Indian production during Apr'08-Sept'08 and 55% during Oct'08-Mar'09 and along with the supporter, it constitutes 100% of the Indian Production. Thus, the applicant shall constitute "domestic industry" for the purpose of the present investigations.

6. The Authority, after examining the above, determines that the applicant constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

### **Countries Involved**

7. The countries involved in the present investigation are Thailand and Japan.

### **Like Article**

8. Applicant has claimed that there is no significant difference in Phenol produced by the applicant and Phenol exported from subject countries. Both products are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both the products are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. Therefore, for the purpose of present investigation, subject goods produced by the applicant are being treated as "Domestic Like Article" to the subject goods imported from subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

### **Normal Value**

9. In the absence of availability of data in respect of the domestic sales in Thailand and Japan, the applicant has constructed normal value on the basis of constructed cost of production of subject goods in subject countries. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicant, subject to adjustment in the higher interest cost claimed in respect of Thailand, and the same has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

**Export Price**

10. The export price of the subject goods from the subject Countries has been claimed on the basis of data obtained from International Business Information Services (IBIS), Mumbai. Price Adjustments have been claimed on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Port Expenses and Inland Freight etc. and scaling down the same to reasonable limits normally adopted by the Authority. There is sufficient evidence of export prices claimed by the applicant for the subject goods from the subject countries.

**Dumping Margin**

11. Normal value and export price have been compared at ex-factory level in respect of the subject countries. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in Thailand and Japan, so arrived is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from subject countries into the Indian market.

**Injury and Causal Link**

12. The applicant has claimed that injury to the domestic industry has not been caused due to the factors other than the dumped imports, as shown below:

- i. The subject goods are being imported primarily from Japan, Thailand and the countries already attracting duty. The imports from other countries are minimal.
- ii. There is some decline in demand in 2008-09 as compared to preceding year but it was significantly higher than 2005-06 and 2006-07. While demand declined, subject imports increased significantly in absolute terms and in relation to demand and production.
- iii. The pattern of consumption with regard to PUC has not undergone any change and therefore could not have contributed to the injury.
- iv. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- v. Technology for production of subject goods has not undergone any change and therefore, not a factor of injury.
- vi. The applicant does not have significant export activities for the product concerned. The export performance of the applicant therefore, has not caused any injury to the domestic industry.
- vii. The productivity of the applicant has declined solely due to dumping.

13. Applicant has submitted that once it is shown that there is an adverse volume and price effect from dumped imports, and the effects of injury caused by dumped imports then, the only basis on which to conclude that the injury is not caused by the dumped imports is through non-attribution analysis, i.e., that other factors have caused the injury. As listed known other factors do not establish that injury has been caused by these other factors, the only inescapable conclusion is that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from a number of sources including subject countries. While the above parameters establish that injury to the domestic industry has not been caused by the other factors, applicant has submitted that the following parameters establish that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

- a) Imports from the subject countries were undercutting the prices of the domestic industry. As a direct consequence, the volume of imports increased significantly.
- b) Increase in the volume of dumped imports resulted in decline in sale volumes of the domestic industry.

- c) Decline in the sales volumes of the domestic industry resulted in decline in the market share of the domestic industry.
- d) Decline in prices of the domestic industry resulted in deterioration in profits, and consequently cash flow and return on capital employed for the domestic industry.

14. There is sufficient evidence that the dumped imports of subject goods from subject countries are, prima facie, causing material injury to the domestic industry.

#### **Initiation of Antidumping Investigation**

15. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject Countries.

#### **Period Of Investigation**

16. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> October 2008 to 30<sup>th</sup> June 2009 (9 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2006-07, 2007-08, 2008-09 and the POI.

#### **Submission of Information**

17. The exporters in the subject Countries, their Government through the Embassy, the importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority  
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce,  
Government of India,  
Room No. 240, Udyog Bhavan,  
New Delhi – 110107.

18. As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations, who can furnish information relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

#### **Time Limit**

19. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

#### **Submission of Information**

20. In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a

statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

### **Inspection of Public File**

21. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by interested parties.

R. GOPALAN, Designated Authority